

गेल गैस ने शुरू की नई सेवा, खुद बनाइए बिल

MEERUT (21 Aug, JNN): ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेल गैस लिमिटेड ने अब गैस बिलिंग की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. कंपनी ने व्हाट्सएप नंबर 91-9650954560 पर नई सेवा शुरू की है, जिसके जरिए उपभोक्ता घर बैठे अपना गैस बिल तैयार कर सकते हैं. गेल गैस लिमिटेड के मेरठ परिक्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को केवल व्हाट्सएप पर चैट शुरू करनी होगी. इसके लिए हेलो, हाय या कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद उसी चैट द्वारा कुछ चरण बताया जाएगा. हाय या हेलो लिखने पर स्वागत का संदेश आएगा. उसमें क्लिक विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करना है. उसके बाद मेनू खुल जाएगा. उस मेनू पर सेल्फ बिलिंग दिखाई देगा, उसी पर टिक करना है. उसके बाद अपना बीपी नंबर मांगा जाएगा उसे दर्ज करें. फिर अपने मीटर की फोटो अपलोड करें. उसके बाद वर्तमान मीटर रीडिंग मांगी जाएगी उसे दर्ज करें. इन चरणों के बाद गैस बिल तुरंत तैयार हो जाएगा.

पैसिव इनकम • इन स्टॉक पर नजर रख सकते हैं निवेशक कोल इंडिया सबसे ज्यादा 7 फीसदी डिविडेंड यील्ड वाला सरकारी शेयर

कुमार गौरव | नई दिल्ली

कोल इंडिया और एनएमडीसी 15 सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड देने वाली सरकारी कंपनियों (पीएसयू) में टॉप पर हैं। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्युरिटीज की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अपने निवेश पर पैसिव (निष्क्रिय) आय चाहने वाले निवेशक इन ऊंचा लाभांश देने वाले पीएसयू शेयरों पर नजर रख सकते हैं।

डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि किसी कंपनी ने अपने वर्तमान शेयर मूल्य का कितने प्रतिशत सालाना लाभांश दिया है। ये डिविडेंड यील्ड लगाई गई पूंजी पर कैपिटल गेन के साथ-साथ एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान करती है। एक्सिस सिक्युरिटीज के मुताबिक कोल इंडिया और एनएमडीसी ने 7 फीसदी लाभांश दिया है जो सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा है।

6 सरकारी कंपनियों ने 5 से 7% तक डिविडेंड यील्ड दिया

कंपनी का नाम	यील्ड	डिविडेंड (12 माह)
कोल इंडिया	7%	26.9 रु.
एनएमडीसी	7%	4.8 रु.
ओएनजीसी	6%	13.5 रु.
नालको	5%	10.0 रु.
आरईसी	5%	19.1 रु.
पावर फाइनेंस कॉर्प	5%	19.5 रु.

4% यील्ड देने वाली सरकारी कंपनियां

- गेल (इंडिया), ■ बामर लॉरी एंड कं.,
- राइट्स, ■ केनरा बैंक

3% यील्ड देने वाली सरकारी कंपनियां

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ■ बैंक ऑफ बड़ौदा, ■ हुडको ■ बीपीसीएल

(स्रोत- एक्सिस सिक्युरिटीज)